मेरा मास्क आपकी रक्षा करता है,

सभी के लिए मास्क
आपका मास्क मेरी रक्षा करता है

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

WASH YOUR HANDS
FREQUENTLY
WITH SOAP AND WATER

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 20 JANUARY TO 26 JANUARY 2021 • VOLUME- 26 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD

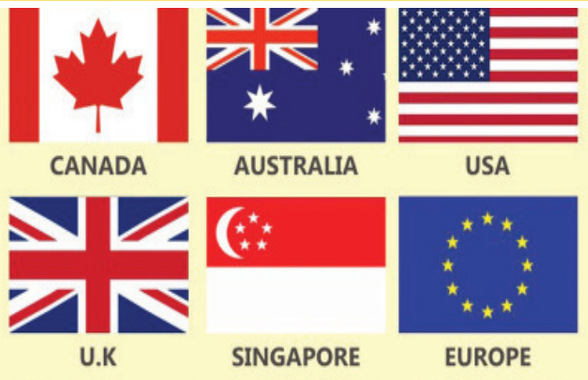

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

एक और बैठक बेनतीजा रही, सरकार ने एक से डेढ़ साल तक कृषि कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर आज लगातार 56वें दिन जारी है। इस बीच आज सरकार और करीब 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की 10वें दौर की बैठक हुई। यह बैठक भी बेनतीजा रही। किसानों और सरकार के बीच अब 22 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि नए कृषि कानून पर दो साल के लिए रोक लगा कर कमेटी बना लें। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों में चर्चा करेंगे। बैठक में एमएसपी पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, कृषि मंत्री ने यहां तक कहा कि अगर कमेटी बनाकर बिंदुवार चर्चा के लिए किसान तैयार होते हैं तो सरकार इस बारे में कोर्ट में हलफनामा भी देने को तैयार हो जाएगी कि कानून एक से डेढ़ साल के लिए स्थगित कर देंगे।

सरकार ने पिछली वार्ता में किसान संगठनों से अनौपचारिक समूह बनाकर अपनी मांगों के बारे में सरकार को एक मसौदा प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के मध्य चल रही वार्ता के बीच उच्चतम न्यायालय ने 11 जनवरी को गतिरोध समाप्त करने के मकसद से चार सदस्यीय समिति का गठन किया था लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने नियुक्त सदस्यों द्वारा पूर्व में कृषि कानूनों को लेकर रखी गई राय पर सवाल उठाए। इसके बाद एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया है।

प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े उद्योग घरानों की 'कृपा' पर रहना पड़ेगा। हालांकि, सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच पर आया पीएम मोदी का बयान, कहा- मैदान में घोर प्रतिद्वंद्वी, बाहर मजबूत साझेदार

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के मैदान में एक-दूसरे के घोर प्रतिद्वंद्वी हैं लेकिन उसके बाहर दोनों देश एक मजबूत साझेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात अपने ऑस्टेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन की ओर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को टेस्ट श्रृंखला में मिली जीत पर दिए गए बधाई संदेश के जवाब में कही।

मॉरिसन ने ट्वीट कर कहा, ''ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला में शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई। खेल के दो सर्वश्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ियों के बीच कड़ी लड़ाई हुई।'' उनके इस ट्वीट के जवाब में मोदी ने लिखा, ''धन्यवाद स्कॉट मॉरिसन। यह बहुत ही रोमांचक श्रृंखला थी जिसमें दोनों ही टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैदान में घोर प्रतिद्वंद्वी हैं और बाहर मजबूत साझेदार।'' भारत ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट श्रृंखला के चौथे और अंतिम मैच में ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर तीन विकेट से हराकर इतिहास रच दिया और बार्डर-गावस्कर ट्राफी अपने पास बरकरार रखी। भारत ने 328 रन का लक्ष्य हासिल कर ये जीत हासिल की और श्रृंखला दो-एक से अपने नाम की।

राजस्थान में 153 और पक्षियों की मौत, बर्ड फ्लू से 17 जिले प्रभावित

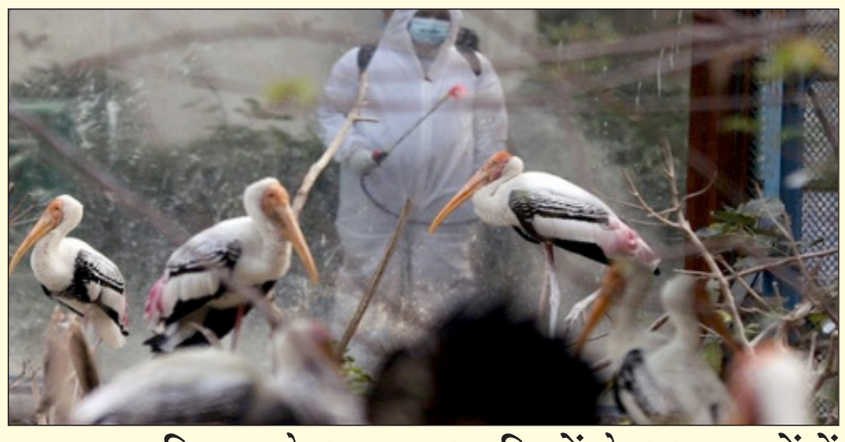

पशुपालन विभाग के अनुसार 27 जिलों के 267 नमूनों में से 67 नमूनों की जांच में संक्रमण पाया गया है

■ जयपुर/ब्यूरो

राजस्थान में बुधवार को 153 और पक्षियों की मौत हो जाने से बर्ड फ्लू के कारण प्रदेश में अब तक कुल 5912 पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के 17 जिले बर्ड फ्लू संक्रमण से प्रभावित है।

पशुपालन विभाग के अनुसार 27 जिलों के 267 नमूनों में से 67 नमूनों की जांच में संक्रमण पाया गया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को 93 कौवे, 8 कबूतर, 21 मोर एवं 31 अन्य पक्षियों की मौत हो गई। राज्य में 25 दिसम्बर से अब तक 5,912 पक्षियों की मौत हो चुकी है।

इनमें 4172 कौवे, 323 मोर, 464 कबूतर तथा 953 अन्य पक्षी शामिल है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बर्ड फ्लू से किसी भी जिले में प्रवासी पक्षी की मौत नहीं हुई है वहीं राज्य में अब तक 59 पोल्ट्री पक्षियों की मौत में जैसलमेर में पांच, कोटा में 17,बूंदी में 33 और जयपुर में चार पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है।

सर्वे का अनुमान- बंगाल में दीदी बनाम मोदी, दादा की एंट्री से बदल सकते हैं चुनावी परिणाम

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच समय-समय पर झड़प की भी खबरें आती है। सी वोटर सर्वे के अनुमान के मुताबिक ममता बनर्जी को इस बार के विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। हालांकि इस सर्वे ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को सत्ता में वापसी का अनुमान जताया है। इस साल 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही हैं तो वहीं भाजपा ममता को मात देने के लिए हर दांव आजमा रही है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस साल बंगाल किसका होगा? विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंगाल की सियासी पारा अभी उफान पर है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच समय-समय पर झड़प की भी खबरें आती है। सी वोटर सर्वे के अनुमान के मुताबिक ममता बनर्जी को इस बार के विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। हालांकि इस सर्वे ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को सत्ता में वापसी का अनुमान जताया है।

इस सर्वे में भाजपा और ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर भी दिखाई गई है। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी को 2 फीसदी वोट का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की तुलना में उनकी पार्टी के 53 सीट भी कम हो सकते हैं।

सर्वे का दावा है कि 43 फ़ीसदी वोट शेयर के साथ ममता बनर्जी की पार्टी को 158 सीटें मिल सकती है। बात भाजपा की करें तो पिछले बार की चुनाव की तुलना में इस बार उसे जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। हालांकि, यह फायदा इतना भी नहीं है कि भाजपा अपने दम पर सरकार बना सकें। पिछले चुनाव के 10.2 फ़ीसदी की तुलना में इस बार भाजपा को 37.5 फीसदी वोट मिल रहे है। इसी के साथ वह तीन के मुकाबले लंबी छलांग लगाकर 102 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस और वामदलों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दोनों ही दलों को इस चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है।

भाजपा के तमाम आरोपों के बावजूद ममता बनर्जी आज भी पश्चिम बंगाल में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सबसे आगे हैं। लगभग 49 फीसदी लोग अब भी ममता बनर्जी को सीएम बनते देखना चाहते हैं। भाजपा के दिलीप घोष सीएम के पसंदीदा चेहरे के तौर पर दूसरे नंबर पर हैं जबकि सौरव गांगुली तीसरे नंबर पर हैं। आपको यह भी बता दें कि राजनीति में सक्रिय नहीं होने के बावजूद सौरव गांगुली तीसरे नंबर पर सीएम चेहरे के रूप में सामने आए हैं।

भाजपा को कोई एक बड़ा सीएम का चेहरा नहीं होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं दिख रहा कि आने वाला पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी हो सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की लगभग 35 फ़ीसदी जनता केंद्र सरकार के कामकाज से बहुत ज्यादा संतुष्ट है तो वहीं 38 फ़ीसदी संतुष्ट हैं। 27 फीसदी लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं।

कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी से लगभग 74 फ़ीसदी जनता संतुष्ट है। पश्चिम बंगाल सरकार के कामकाज से वहां की जनता खुश नहीं है। बावजूद इसके ममता बनर्जी की लोकप्रियता बरकरार है। 49 फ़ीसदी जनता ने बंगाल सरकार के कामकाज से असंतुष्टी जताई है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। वर्तमान परिस्थिति में देखे तो भाजपा और ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है। अगर पूर्व क्रिकेट कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भाजपा में शामिल होते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे किया जाता है तो इससे भगवा पार्टी को बहुत फायदा होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में मोदी बनाम दीदी फिलहाल यही ट्रेंड है। आगे की परिस्थितियों में क्या बदलाव होते हैं यह देखने वाली बात होगी।

24 घंटे के अंदर लूट ,डकैती या अपहरण की वारदात को हल करने वाली पंजाब पुलिस के होते कैसे चल रहा है अवैध शराब और नशा तस्करी का धंधा जांच का विषय

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

कांग्रेस की सरकार को पंजाब में सत्ता में आये लगभग 4 साल पुरे हो चुके है लेकिन जो बीमारी पिछली अकाली -भाजपा सरकार के समय हल न होने के कारण उन्हें सत्ता से दूर कर गयी थी वही बीमारी मौजूदा सरकार के समय रोज सुनने में मिलती है अक्सर आपको समाचार पत्रों में पंजाब के कई जिलों में आये दिन सुनने या पड़ने को मिलेगा की पंजाब पुलिस द्वारा बारी मात्रा में अवैध शराब या अलग अलग तरह का नशा पकड़ा गया और गिरफ्तार किये गए लोगों में ज्यादातर आज कल की युवा पीढ़ी सामने आती है

जो की किसी न किसी कारण इस तरह के अवैध धंधे में लिप्त पाई जाती है कई बार इस विषय के बारे में चर्चा होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा बताया गया की जेल से छूटने के बाद ज्यादा तर लोग फिर इसी अवैध धंधे को शुरू कर देते हैं और कोई इतने सख्त कानून न होने के करण बार बार पकडे जाने के बाद उन्हें जमानत मिल जाती है सोचने वाली बात यह है की जब भी पंजाब के किसी जिले में बड़ी लूट,डकैती या बच्चा अपहरण जैसी कोई वारदात होती है।

उसी वक्त पंजाब पुलिस जो की पुरे देश में दूसरे राज्यों से ज्यादा सक्षम मानी जाती है हरकत में आती है और 24 घंटे के अंदर ज्यादातर ऐसे मामलो को हल करने में सफल हो जाती है और उसी वक्त लोगों से और अपने उच्च अधिकारियों से शाबाशी और प्रशंसा पत्र भी हासिल करती है लेकिन अब तो पंजाब पुलिस जो की बॉर्डर के साथ लगता राज्य होने के कारण इतनी हाईटेक हो चुकी है फिर भी कहीं न कहीं अवैध शराब हो या नशा तस्करी से जुड़े हुए बड़े-बड़े लोगो को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है।

अगर पुलिस चाहे तो किसी शहर या गाओं में उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता यह पंजाब में रहते हर एक व्यक्ति ने कोरोना काल में लोकडाउन के दौरान देखा भी और समझा भी क्या पुलिस को अपना काम सही ढंग से न करने देने के पीछे राजनितिक दबाव होता है या विभाग के अंदर ही दाल में कुछ काला है यह सब कुछ जांच का विषय है।

लेफ्टिनेंट भावना कंठ रचेंगी इतिहास, Republic day पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनेंगी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। वह भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की झांकी का एक हिस्सा होगीं जो स्वदेशी तेजस, लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल और सुखोई 30रूधढ़ लड़ाकू विमान के मॉक-अप का प्रदर्शन करेगी।

भावना कांत रचने जा रही हैं इतिहास

लेफ्टिनेंट भावना कंठ वर्तमान में राजस्थान के एक एयरबेस में तैनात है जहां वह मिग -21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है, कंठ भी भारतीय वायुसेना में पहली महिला

लड़ाकू पायलटों में से एक है। अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ, कंठ को 2016 में पहली महिला लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने गणतंत्र दिवस पर झांकी का हिस्सा बनने के बारे में बात करते हुए कहा मैं बचपन से ही टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देखती थी और यह गर्व की बात है कि अब मैं इसमें भाग ले रही हूं। मैं राफेल और सुखोई सहित अन्य फाइटर जेट्स उड़ाना पसंद करूंगी।

दखल

यह जरूरी नहीं कि सभी के पास महल हों, पर यह बहुत जरूरी है कि बुनियादी विकास से कोई अछूता न रहे। जब ऐसा हो जाएगा तभी सर्वोदय होगा और लोक सशक्तिकरण होगा। सुशासन लोक विकास की कुंजी है जो शासन को अधिक खुला और संवेदनशील बनाता है। ऐसा इसलिए है ताकि सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सरकारें खुली किताब की तरह रहें और देश की जनता को दिल खोल कर विकास दें।

सुशासन के सही अर्थ पर हो बात

सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस उद्देश्य के साथ नवीन लोक प्रबंधन की सैद्धांतिक आधारशिला रखी थी ताकि पुराने स्वरूप से विकास करने वाले शासन को नया रूप दिया जा सके। इसका उद्देश्य ऐसी सरकार और प्रशासन तैयार करना था जो अपनी भूमिका 'नाव खेने' की जगह 'स्टीयरिंग' संभालने के रूप में बदल ले। जब सड़क खराब हो तो ब्रेक गति पर नियंत्रण रखते हैं और जब सब कुछ अनुकूल हो तो यात्रा सुगम हो जाती है। जाहिर है, ऐसी शासन पद्धति में लोक कल्याण की भावना में बढ़त और लोक सशक्तिकरण के आयामों में उभार को बढ़ावा मिलता है। इस बात का सभी समर्थन करेंगे कि 21वीं सदी के 21वें साल पर तुलनात्मक विकास का दबाव अधिक है, क्योंकि इसके पहले का वर्ष महामारी के चलते उस आईने की तरह चटक गया है जिसमें सूरत बिखरी-बिखरी दिख रही है। यदि इसे एक खूबसूरत तस्वीर में बदला जाए तो ऐसा सर्वोदय और सशक्तिकरण के चलते ही संभव होगा, जिसकी बाट उम्मीद से जनता जोह रही है।

तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को नया रूप लेना जरूरी है। न्यू इंडिया की अवधारणा इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में हो रहे अनवरत परिवर्तनों को देखते हुए न केवल दक्ष श्रमशक्ति, बल्कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांवों की ओर भी कदमताल तेजी से करना होगा। यह दौर मौद्रिक और वित्तीय कदम उठाने के मामले में और समस्याओं से बंध चुके लोगों को बहाल करने का है। ऐसे में सर्वोदय इसकी प्राथमिकता है और यह सुशासन पर पूरी तरह टिका है। सर्वोदय सौ साल पहले गांधी दर्शन से उपजा शब्द है, मगर इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। सर्वोदय एक ऐसा विचार है जिसमें सभी के हितों की भारतीय संकल्पना के अलावा सुकरात की सत्य साधना और रस्किन के अंत्योदय की अवधारणा मिश्रित है।

सर्वोदय सर्व और उदय के योग से बना शब्द है जिसका संदर्भ सबका उदय और सब प्रकार के उदय से है। यह सर्वांगीण विकास को परिभाषित करने से ओतप्रोत है। आत्मनिर्भर भारत की चाह रखने वाले शासन और नागरिकों दोनों के लिए यह एक अंतिम सत्य भी है। सममसामयिक विकास की दृष्टि से देखें तो समावेशी विकास के लिए सुशासन एक कुंजी है, लेकिन सर्वज्ञ विकास की दृष्टि से सर्वोदय एक आधारभूत संकल्पना है। बेशक देश की सत्ता पुराने डिजाइन से बाहर निकल गई है, पर कई चुनौतियों के चलते समस्या समाधान में अभी बात अधूरी है। सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है जो लोक कल्याण को बढ़ावा देती है और जिसमें नागरिक सशक्तिकरण उन्मुख होता है। बीते वर्ष कोरोना महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई। लेकिन अब सकारात्मक संकेत आने लगे हैं। हालांकि बेरोजगारी, बीमारी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जैसी तमाम बुनियादी समस्याएं अभी भी कायम हैं। गरीबी और भुखमरी की ताजी सूरत भी स्याह दिखाई देती है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हम भुखमरी के संकट से निजात नहीं पा सके हैं। पिछले साल की रिपोर्ट में 107 देशों में भारत 94वें पायदान पर रहा, जबकि 2014 में 55वें पायदान पर था। पांच साल में हालात का इतना बिगड़ना चिंता और सवाल खड़े करता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, फिर पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि प्रधान होना और सात दशकों के भीतर ऐसी बारह योजनाओं को देखा जा सकता है जिनमें गरीबी उन्मूलन से लेकर समावेशी विकास तक की भी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल हैं। बावजूद इसके देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित और इतने ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगले साल तक किसानों की आमदनी भी दोगुनी करने की बात है और दो करोड़ से अधिक घर भी 2022 के भीतर ही दिए जाने हैं। बुनियादी विकास की चुनौतियों और शहरी व ग्रामीण विकास की अवधारणा के अलावा कई तकनीकी विकास से भी देश को ओतप्रोत होना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों और उद्योगों को मजबूती देना, साथ ही किसान हितैषी योजनाओं को भी सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहन की जरूरत है। सबसे बड़ी बात सरकार और किसान के बीच विकासात्मक सुलह को हासिल करना है, ताकि सर्वोदय की शुचिता को खतरा न हो।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र धराशायी हो रहे थे, तब कृषि ही ऐसा क्षेत्र था जिसने अपनी विकास दर को 3.7 फीसद से ऊपर रखते हुए देश को अन्न से भर दिया। संकटकाल में अन्नदाताओं की प्रासंगिकता और खेत-खलिहानों की उपयोगिता कहीं अधिक समझ में आई। जाहिर है अपने हिस्से के विकास की बाट तो खेत-खलिहान भी जोह रहे हैं। सुशासन लोक विकास की कुंजी है जो शासन को अधिक खुला और संवेदनशील बनाता है। अब ऐसा इसलिए है ताकि सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सरकारें खुली किताब की तरह रहें और देश की जनता को दिल खोल कर विकास दें। मानवाधिकार, सहभागी विकास और लोकतंत्रीकरण के साथ सर्वोदय व सशक्तिकरण का महत्व सुशासन की सीमा में ही है। सुशासन के लिए महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी होता है और ऐसा तभी संभव है जब पूरी प्रणाली पारदर्शी और ईमानदार हो। कानून ने विवेकपूर्ण व तर्कसंगत सामाजिक नियमों और मूल्यों के आधार पर समाज में एकजुटता की स्थापना की है और शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो कानून से अछूता हो।

वर्तमान दौर कठिनाइयों का तो है, पर बुनियादी विकास ऐसे तथ्यों और तर्कों से परे होते हैं। देश में नौकरियों के 90 फीसद से ज्यादा अवसर सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम क्षेत्र मुहैया कराता है। इस क्षेत्र की अहमियत को देखते हुए सरकार ने कई कदमों की घोषणा पहले के बजट में भी की है। वैश्विक महामारी के कारण बाजार में घटी हुई मांग के सदमे से उबरने का दबाव एमएसएमई क्षेत्र पर भी साफ देखा जा सकता है। यह क्षेत्र जितनी शीघ्रता से पटरी पर लौटेगा, उतनी ही तेजी से देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। गौरतलब है कि सरकार देश को 50 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से समावेशी विकास और रोजगार सृजन के लिए समर्पित है। यह आसान नहीं है। इसके लिए उद्यमिता को बढ़ावा और तकनीक में नवाचार जरूरी होगा। सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सर्वोदय का प्रतीक कहा जा सकता है।

मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं भी एक नई सूरत की तलाश में है। जिस तरह अर्थव्यवस्था और व्यवस्था को चोट पहुंची है, उसकी भरपाई आने वाले दिनों में तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था नए स्वरूप में ढलेगी। कुल मिलाकर विकास के सभी प्रकार और सर्वज्ञ विकास और सब तक विकास की पहुंच अभी अधूरी है और इसे पूरा करने का दबाव 2021 या आगे आने वाले वर्षों पर अधिक इसलिए रहेगा क्योंकि 2020 का घाटा जल्दी जाने वाला नहीं है। ऑक्सफोर्ड इकोनोमिक्स की पड़ताल भी यह बताती है कि 2025 तक भारत की विकास दर पांच फीसद से कम रह सकती है।

विचार

अमेरिका में अब बाइडेन युग

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद कई देशों की उम्मीदें अमेरिका के साथ नए सिरे से संबंध स्थापित करने की है। भारत भी अपने ढंग से नई परिभाषा गढ़ने में जुटा हुआ है।

दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका एक नए इतिहास में प्रवेश करने का जा रहा है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी। इन हालात में, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन द्वारा भारत का समर्थन सिर्फ स्वागतयोग्य कदम से कुछ अधिक ही है। पिछले सप्ताह भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा, मैं हमेशा भारत के साथ खड़ा रहूंगा और इसके अपनी सीमाओं पर सामना कर रहे खतरों में इसका साथ दूंगा। भले ही उन्होंने पूर्वी लद्दाख में टकराव का जिक्र नहीं किया हो, लेकिन सीमाओं पर भारत की स्थिति के लिए उनका आम समर्थन भरोसा जगाता है और अगर वो नवंबर में अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अमेरिकी नीति में एक नया आयाम ला सकता है।

विदेश नीति के अनुसार, बाइडेन पहले से ही एक काबिल टीम बना चुके हैं, जिसमें 20 भारतीयों को जगह दी गई है। बाइडेन की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश नीति पर कुछ ज्यादा विवादास्पद कदमों को वापस लेना होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की मौजूदा स्थिति का समर्थन भारत-अमेरिका संबंधों में आगे बढ़ने का एक बड़ा कदम होगा। 77 वर्षीय बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले यह रिकार्ड डोनाल्ड ट्रंप के नाम था, जो 70 वर्ष की उम्र में 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। बाइडेन की इस चुनावी जीत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पिछले तीन दशक के अमेरिकी इतिहास के ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जो राष्ट्रपति रहते हुए अपना चुनाव हारे हों। इससे पहले 1992 में जॉर्ज बुश सीनियर राष्ट्रपति रहते हुए अपना चुनाव बिल क्लिंटन से हार गए थे। इसके बाद बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर और बराक ओबामा ने फिर से चुनाव जीता था। ये तीनों लगातार दो बार चुनाव जीतकर 8-8 वर्ष तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे।

अमेरिका के 100 वर्षों के इतिहास में अब तक सिर्फ चार राष्ट्रपति ही ऐसे हुए हैं, जिन्हें अपने दूसरे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ट्रंप की चुनावी हार के बाद से ही भारत-अमेरिकी संबंधों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। भारत के अंदर एक बड़ा तबका ट्रंप की हार को नरेंद्र मोदी की हार के तौर पर प्रचारित कर रहा है। यह राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रंप का चुनावी प्रचार करके प्रधानमंत्री मोदी ने जो गलती की थी, उसका खामियाजा अब भारत को उठाना पड़ सकता है। सवाल यह है कि वाकई ऐसा होने जा रहा है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। मगर अभी तो यही कहा जा सकता है कि बाइडेन भारत के साथ बैर लेने की स्थिति में नहीं होंगे। अमेरिका को जिस तरह से चीन को काबू में करना है, उसमें भारत से बड़ा मददगार और कोई नहीं हो सकता।

विनाश रचती जंगल की आग

पिछले साल आस्ट्रेलिया के बहुत बड़े इलाके में खड़े जंगल तबाह हो गए। भारत में भी पिछले साल आग की कई घटनाएं घटीं। कुछ बड़ी घटनाओं में अनेक लोग मारे गए। यों आग की घटनाएं अब दुनिया में साल के बारहों महीने होती रहती हैं, पर गर्मी में कुछ ज्यादा घटती हैं, जिनसे करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है, मवेशी और सैकड़ों लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। सरकारों के आग पर काबू पाने और मुस्तैदी के सारे दावे धरे रह जाते हैं। पिछले कुछ सालों में अब तक आग की 22 हजार से अधिक घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में घट चुकी हैं, जिसमें करोड़ों की संपत्ति खाक हो चुकी है। मवेशी और जन-धन की जो हानि हुई, वह अलग। इधर कुछ सालों में देश के विभिन्न हिस्सों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

यों तो मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी आग से जंगल तबाह होते रहे हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इन दोनों पहाड़ी राज्यों में तबाही देखने को मिलती है, वैसे अन्य किसी राज्य में नहीं। पिछले 30 वर्षों में आग की हजारों छोटी-बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं, जिनसे लाखों हेक्टेयर जमीन में खड़े जंगल प्रभावित हुए। जैविक विविधता नष्ट हुई है और जीव-जंतु मारे गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार भारत के 50 फीसद जंगलों को आग से खतरा है, जिसमें अधिकतर जंगल हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के हैं। जब पांच वर्ष पहले कार्बेट जल कर खाक हो गया था, तब आग की चपेट में आकर लाखों जीव-जंतु मारे गए व बेशकीमती औषधियां आग की भेंट चढ़ गई थीं।

पिछले दस सालों में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में इस तरह की कई भीषण घटनाएं घटीं, लेकिन उनसे राज्य सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा। शहरों में तो दमकल के जरिए आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में काबू पाना मुश्किल होता है। आमतौर पर गर्मी के महीनों में हर वर्ष जंगली क्षत्रों में आग लगती ही है। कई बार सूखे पत्तों और घनी झाड़ियों को जलाने के लिए आग लगाई जाती है। यह माना जाता है कि स्थानीय निवासियों द्वारा छोटे इलाकों में सूखे पत्तों और छोटी सूखी वनस्पतियों को जलाने से विनाशकारी आग की घटनाएं नहीं होती हैं। पर्यावरण की क्षति, वन क्षेत्र की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के विनाश का भी खतरा नहीं रहता। राज्य और केंद्र सरकार को इस तरह के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करके छोटे इलाकों के पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले खर-पतवारों को जलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धीरे-धीरे यह पंरपरा बन जाएगी और जगलों की विविधता और हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर पिघलने की बढ़ती समस्या को भी काफी हद तक रोका जा सकता है।

हिमाचल, जम्मू, छत्तीसगढ़, असम, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी हर वर्ष जंगल जलते हैं और मनुष्य अपने स्वार्थ में तमाशबीन बना दिखता है। समस्या एक स्तर पर हो, तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। लेकिन यहां तो समाधान करने वाले ही समस्या पैदा कर रहे हैं। समस्या एक स्तर पर हो, तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। लेकिन यहां तो समाधान करने वाले ही समस्या पैदा कर रहे हैं।

पहाड़ी इलाकों के रहवासियों का पालन-पोषण जंगल ही करते रहे हैं। फल-फूल, मेवे, औषधियां, जलाऊ व इमारती लकड़ियां भी जंगलों से आराम से मिल जाती थीं। कभी जंगल लोगों को पालते थे और लोग जंगलों की सुरक्षा करते थे। 1970 के दशक में जंगल बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए, जिसमें शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। जंगलों की रक्षा के लिए यह आंदोलन दुनिया भर की महिलाओं के लिए नजीर बन गया। 1988 में केंद्र सरकार ने जो वन नीति बनाई थी उससे जंगलों को संरक्षित करने और विस्तार करने में सहूलियत तो मिली, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह वनों में माफिया, तस्करों और वन विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत से लूट मची, उससे उत्तराखंड बनने का उद्देश्य खंड-खंड हो गया।

उत्तराखंड में देश-विदेश की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां की अमूल्य संपदा का दोहन कर पूरे इलाके को खोखला करने में लगी हुई हैं। रोजगार देने और खुशहाली का नया दौर शुरू करने का सब्जबाग दिखाने वाली ये कंपनियां राज्य सरकार से खाद-पानी पाती रही हैं। सरकार अवैध निर्माण, जगली जंतुओं के शिकार, अवैध खनन और वन की अमूल्य औषधियों और लकड़ियों की तस्करी रोकने में विफल रही है। पहाड़ के निवासियों द्वारा उत्तराखंड निर्माण के समय देखे गए स्वप्न जंगलों के साथ लगातार जलते आए हैं। हर बार चुनाव के समय हर पार्टी उत्तराखंड को सबसे खुशहाल राज्य बनाने का वादा करके सत्ता में आती है और सत्ता मिलते ही वह अपना नफा-नुकसान केवल पर्यटन को बढ़ावा देने और नई-नई देशी-विदेशी कंपनियों के जरिए लाभ कमाने पर सारा ध्यान केंद्रित करती है। शुभ सोचने और करने पर कभी गौर ही नहीं किया जाता। इस प्रदेश की मूल समस्याओं के लिए ठोस, दूरगामी योजनाएं नहीं बनाई जातीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रदेश की समस्याएं पिछले बीस वर्षों में अधिक तेजी के साथ बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश को खंडित करके जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, उस वक्त इस इलाके के लोगों को लगा था कि उनकी एक मुराद पूरी हो गई, अब कहीं अधिक तेजी के साथ इस प्रदेश को अपने स्वप्नों का प्रदेश बनाएंगे। राजनेताओं ने भी जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे। उसमें एक वादा यह भी था कि इस प्रदेश की मूलभूत समस्या- सड़क, बिजली और पानी को हल करने को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा।

पलायन के लिए किसी को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसमें से एक भी समस्या हल नहीं हो पाई, बल्कि दूसरी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाढ़, बारिश और वन की आग की समस्याओं का लगातार बढ़ते जाना, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इन समस्याओं का जिम्मेदार 95 प्रतिशत तक मानव ही है, जो अपने स्वार्थ में इस क्षेत्र की विविधता का दोहन करता आ रहा है। जंगल जला, तो इस इलाके का आधार ही जल कर खाक हो गया। देवभूमि कहा जाने वाला यह पहाड़ी प्रदेश अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और इसके आंसू पोंछने वाला न तो शासन, प्रशासन आगे आ रहा है और न तो स्थानीय लोगों को साथ लेकर कोई नया आंदोलन खड़ा हो पा रहा है। परिणाम यह हो रहा है कि आग की विकराल होती लपटें पहाड़ों को पिघला रही हैं और निकलते धुंए हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों पर जमते जा रहे हैं। इससे कार्बन के कण गर्मी अधिक सोख रहे हैं, जिससे तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है। इससे जहां टिहरी बांध पर दबाव बढ़ेगा, वहीं निचले इलाकों में बाढ़ के विनाशकारी रूप लेने की अशंका बढ़ गई है।

दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में आग के कारण उत्तर भारत का तापमान 0.2 डिग्री बढ़ सकता है और इससे मानसून प्रभावित हो सकता है। जंगल की आग को रोकने के लिए यों तो अनेक नई-नई तकनीकें इस्तेमाल की जाने लगी हैं, जिसमें कृत्रिम वर्षा कराना, विमान और ड्रोन से रासानिक झाग का छिड़काव व मिट्टी का छिड़काव प्रमुख हैं। लेकिन ये तरीके बहुत महंगे और भारत जैसे गरीब देश के लिए अभी संभव नहीं दिखते। दरअसल, जगलों में आग लगने की समस्या केवल उत्तराखंड की नहीं है। इसलिए अब सरकारों को एक मुकम्मल नीति के साथ आगे आना होगा और जंगलों को बचाना होगा।

ट्विटर

अमेरिका और भारत के संबंध वर्षों पुराने हैं और यह व्यक्ति आधारित नहीं है। बाइडेन प्रशासन के साथ भारत नई इबारत लिखेगा और रिश्तों को मजबूत करेगा।

एस. जयशंकर, विदेश मंत्री

बाइडेन प्रशासन भारत के साथ आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित है। दोनों देशों के बीच जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। भारत अमेरिका का खास दोस्त है।

कमला हैरिस, निर्वाचित उपराष्ट्रपति

सत्यार्थ

योगी बनाम सामान्य पुरुष

बात काफी पुरानी है। एक गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक तालाब था। इस गांव की महिलाएं उसमें स्नान करने और कपड़े धोने के लिए रोज ही जाया करती थीं। एक दिन जब महिलाएं उस तालाब के किनारे पर अपने कपड़े रखकर उसमें स्नान करने लगीं तो संयोग से उसी समय महावीर स्वामी और उनका शिष्य गोशालक उधर से ही गुजर रहे थे। महावीर आगे-आगे चले जा रहे थे और गोशालक उनके पीछे-पीछे रास्ते में पेड़ों से फल तोड़ता और इधर-उधर देखता हुआ चल रहा था। तभी

तालाब में स्नान कर रहीं महिलाओं में से एक ने कहा- देखो, कोई पुरुष आ रहा है। तब सभी महिलाओं ने अपना सिर पानी से ऊपर उठाकर देखा, तो बोलीं- अरे! ये तो महावीर हैं। वे फिर से उसी तरह स्नान करने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्हें गोशालक आता दिखा। इस बार उन्होंने बाहर आकर अपने-अपने कपड़े पहन लिए। उन महिलाओं के साथ एक कम उम्र की तरुणी भी थी। उसने पूछा-पहले जब योगी पुरुष इधर से गुजरा, तब तो तुम सब चुपचाप स्नान करती रहीं। फिर, उसी का शिष्य आया, तो तुम सब कपड़े पहनने लगीं, ऐसा क्यों? तब उनमें से एक बड़ी उम्र की महिला बोली-पहला योगी था, उसकी दृष्टि में स्त्री-पुरुष का भेद खत्म हो गया था। दूसरा पुरुष गोशालक था, उसके मन में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं मिटा था। इसलिए पर्दा करना जरूरी था। आशय यह है कि पुरुष स्त्री को मान-मर्यादा में रहने की सलाह तो देता है और उन पर बंदिशें तो लगाता है, लेकिन यही सब वह अपने ऊपर लागू नहीं करता। यदि पुरुष खुद मर्यादा में रहें और स्त्री-पुरुष में भेद करना छोड़ दें, तो फिर न स्त्रियों पर कोई बंदिश लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी।

न्यूज

संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़े : मिश्र

जयपुर, (एजेंसी)। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर तेजी से हो रहे बदलावों और राष्ट्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति की जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की जरूरत है। श्री मिश्र मंगलवार को सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्यों और इस दौर में इसकी प्रासंगिकता पर सभी स्तरों पर व्यापक विमर्श की जरूरत है। बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की कई उपलब्धियां रही हैं, परंतु कोविड-19 महामारी जैसे बहुत से अवसर ऐसे भी आए हैं, जब संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता हुई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को समान रूप से राष्ट्रों के विकास के लिए साझा हितों के लिए कार्य करने पर जोर दिया।

सिन्हा ने ली विद्युत विनियामक आयोग अध्यक्ष पद की शपथ

पटना, (एजेंसी)। शिशिर सिन्हा ने मंगलवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद को शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर शिशिर सिन्हा एवं इसके सदस्य सुभाष चंद्र चौरसिया की नियुक्ति के लिए उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य रमेश कुमार चौधरी, राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू, ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजीवन सिन्हा, बिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार, ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव बिनोदानन्द झा, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सचिव रामेश्वर प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे।

मरे कौए में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 26 तक बंद रहेगा लाल किला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लाल किले में मृत मिले कौओं में से एक के नमूने में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद इस ऐतिहासिक इमारत में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक राकेश सिंह ने बताया कि 10 जनवरी को लाल किले में करीब 15 कौवे मृत पाए जाने के बाद नमूने जांच के लिए जालंधर स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए थे। राकेश सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान ने भी नमूने की जांच में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ऐहतियात के तौर पर लाल किले को दर्शकों के लिए 26 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। विभाग ने एक आदेश में कहा है कि बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने की पशुपालन विभाग की योजना के अनुसार लाल किले को 'अलर्ट जोन' और संक्रमित क्षेत्र में रखा गया है।

जूता कांड के विधायक और पूर्व सांसद को हाईकोर्ट से राहत

संतकबीरनगर, (एजेंसी)। पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी और मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच हुए विवाद और जूता कांड में दोनों नेताओं को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। लंबी जद्दोजहद के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले को खत्म कर दिया है। वहीं दोनो नेताओं के विरुद्ध जारी वारंट भी निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय से दोनो नेताओं को काफी राहत मिली है। जिला योजना की बैठक में तत्कालीन सांसद शरद त्रिपाठी और मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान जूता भी चला, जिसमें कलेक्ट्रेट सदर नाजिर सैयद नफीसउल हसन ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस द्वारा विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट लगाई गई थी। पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में मामले को खत्म करने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसे विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दीपकांत मणि ने अस्वीकार कर अग्रिम विवेचना कराने का आदेश दिया।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

पड़ोसी देशों को भी आज से वैक्सीन देने जा रहा भारत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एक बार फिर पड़ोसी धर्म निभाने का फैसला किया है। भारत ने अनुदान सहायता के तहत बुधवार से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरीशस के संबंध में जरूरी नियामकीय मंजूरी का इंतजार है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत आगामी हफ्ते, महीने में चरणबद्ध तरीके से सहयोगी देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि दूसरे देशों को टीके की आपूर्ति करते समय यह तय किया जाएगा कि देश के टीका निर्माताओं के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने पर्याप्त भंडार हों। पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन आपूर्ति को लेकर कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की जरूरत को पूरा करने भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत का गहरा सम्मान है। कई देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति बुधवार से

शुरू होगी और अन्य को आने वाले दिनों में। पाकिस्तान ने भी भारत में निर्मित कोविशील्ड को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, लेकिन वह वैकेसीन के लिए मुंह ताक रहा है।

भूटान समेत कई देशों को फ्री में मिलेगी वैक्सीन

सूत्रों के मुताबिक, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने ऐलान किया कि भारत सरकार ने उन्हें कोरोना की वैक्सीन फ्री में देगी। इसके अलावा, 20 जनवरी को बांग्लादेश को भी भारत की तरफ से कोरोना कोविशील्ड की 2 मिलियन डोज बतौर गिफ्ट मिलेगी। इतना ही नहीं, नेपाल को भी भारत सरकार फ्री में कोरोना वैक्सीन देगी। इस तरह से चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी के खिलाफ भारत ने बहुत लंबी लकीर खींच दी है, जिसका असर पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी दिखेगा।

भारत अपनी डिप्लोमेसी को भी दे रहा है एक नया आयाम

नाम न छापने की शर्त पर उनमें से एक अधिकारी ने कहा कि भारत सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की करीब 10 मिलियन खुराक अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे देशों को दान कर सकता है। बता दें कि भारत पड़ोसी देशों की मदद कर न सिर्फ मानवता धर्म निभा रहा है, बल्कि अपनी डिप्लोमेसी को भी एक नया आयाम दे रहा है।

नई रिलीज वेब सीरीज तांडव का विरोध

भाजपा नेता राम कदम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को मुंबई में नई रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।

महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित

जनता दल (युनाइटेड) के कार्यकर्ताओं ने पटना में पार्टी कार्यालय में पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की।

वॉलेट में रखा है 22 करोड़ डॉलर का बिटकॉइन, किंतु पासवर्ड भूल गए हैं थॉमस

जर्मनी के शख्स ने नहीं मानी हार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। हम सभी जानते हैं कि दैनिक उपयोग के उपकरणों और खातों के लिए पासवर्ड याद रखना कितना थकाऊ हो सकता है। इससे भी अधिक कष्टप्रद क्या हो सकता है, जब किसी को अपना पासवर्ड बदलना पड़े, क्योंकि वह अपना पुराना पासवर्ड भूल गया है। इसके लिए जरूरी स्टेप्स काफी बोझिल होते हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस कारण से किसी को करोड़ों का नुकसान हो गया हो? जी हां, यह सच है। कुछ ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है।

रिसेट करने के आठ प्रयास भी फेल

जर्मनी के रहने वाले एक प्रोग्रामर स्टीफन थॉमस की कहानी सुनकर आप भी कुछ देर के लिए परेशान हो जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले थॉमस ने अपने लगभग 22 करोड़ डॉलर के बिटकॉइन के लिए पासवर्ड भूल गए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस की इस कहानी को जानकर आप भी रोमांचित हो उठेंगे।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग दस साल पहले थॉमस को कैसे क्रिप्टोक्यूरेंसी कैसे काम करती है, इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए 7,002 बिटकॉइन दिए गए थे। उस समय उसकी कीमत महज कुछ डॉलर की थी। अब 7,002 बिटकॉइन की कीमत 220 मिलियन डॉलर हो चुकी है, लेकिन किस्मत ने थॉमस के साथ धोखा दिया। थॉमस एक छोटी सी हार्ड ड्राइव जिसमें डिजिटल वॉलेट के पासवर्ड सेव थे, का पासवर्ड भूल जाते हैं।

थॉमस ने पासवर्ड को एक कागज के टुकड़े पर भी लिखा था, जो कि गलत लिखा गया है। उनके पास पासवर्ड का अनुमान लगाने के दस प्रयास हैं, जिसमें से उन्होंने पहले ही आठ का उपयोग कर लिया है। दो और असफल प्रयासों के बाद, पासवर्ड खुद को एन्क्रिप्ट करेगा, जिससे वॉलेट तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। इन परिस्थितियों से थॉमस ने एक सकारात्मक सबक ली है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कैसे अपने आत्म-मूल्य को आगे बढ़ाने के लिए परिभाषित करने जा रहा था।

त्रिपुरा में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ बनाया गया 42वां कोकबोरोक दिवस

अगरतला, (एजेंसी)। त्रिपुरा में मंगलवार को कई श्रृंखलाबद्ध और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 42वां कोकबोरोक दिवस बनाया गया। कोकबोरोक दिवस दरअसल कोकबोरोक भाषा को मान्यता मिलने के मौके पर मनाया जाता है। यह जनजातियों की एक भाषा है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री बिप्लव देव, उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने भी राज्य के लोगों को कोकबोरोक दिवस की बधाई दी। राजस्व मंत्री एनसी देववर्मा ने अगरतला के उमाकांत अकादमी में मंगलवार को सुबह पारंपरिक तौर-तरीकों के साथ एक रंगीन रैली को हरी झंडी दिखाई। इसमें राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया।

चीन और डब्ल्यूएचओ की वजह से खत्म हुईं लाखों जिंदगियां

जांच टीम ने कहा- कंट्रोल हो सकता था कोरोना वायरस

नई दिल्ली ■ एजेंसी

चीन से निकलकर पूरी दुनिया में जिस कोरोना वायरस ने तबाही मचाई, उसे लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की निष्क्रियता से लाखों जिंदगियां खत्म हुई हैं। एक स्वतंत्र पैनल (इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है अगर चीन चाहता तो कोरोना वायरस को महामारी बनने से रोका जा सकता था, मगर उसने समय रहते काबू नहीं किया। इतना ही नहीं, इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। वैश्विक महामारी की जांच करने वाले इस स्वतंत्र समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि जब चीन में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन और बीजिंग तेजी से काम कर सकते थे। मगर

उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन दोनों की लापरवाही की वजह से दुनियाभर में कोरोना फैला। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में कहा कि महामारी प्रकोप के प्रारंभिक चरण के क्रोनोलॉजी का मूल्यांकन इस बात की ओर इशारा करता है कि शुरुआती संकेतों के बाद अधिक तेजी से काम करने की आवश्यकता थी।

संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी समितियों को नहीं दी सूचना

रिपोर्ट में पैनल ने पाया कि यह स्पष्ट दिखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को जनवरी महीने में ही चीन में स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अधिक बलपूर्वक लागू किया जा सकता था। इस पैनल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी आलोचना की है और कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने 22 जनवरी, 2020 तक अपनी आपातकालीन समिति को भी इस महामारी संकट की सूचना नहीं दी और न ही बैठक बुलाई। और समिति नोवल कोरोना वायरस को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में भी समय से पहले घोषित करने में असफल रही थी।

समिति आपातकाल की घोषणा पर सहमत क्यों नहीं हो पाई?

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि समिति जनवरी के तीसरे सप्ताह तक क्यों नहीं मिली और न ही यह स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर सहमत क्यों नहीं हो पाई? जब से कोरोना वायरस का संकट पूरी दुनिया में गहराया तब से ही इसके जवाबी कार्रवाई में ढीलापन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना हो रही है। महामारी को आपदा घोषित करने और फेस मास्क को अनिवार्य करने में देरी से उठाए गए कदमों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना हो रही है। अमेरिकी की आलोचना तो जगजाहिर है।

ट्रंप प्रशासन ने अपनाया था सख्त रुख

यही वजह है कि महामारी के शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कोरोना को लेकर चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति सख्त रुख अपनाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन का कठपुतली तक कह दिया था और डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी बंद कर दी थी। बता दें कि विशेषज्ञों के इस पैनल में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलेफ भी शामिल हैं। मई में इसकी आखिरी और फाइनल रिपोर्ट आएगी।

पाक एयरलाइंस के यात्री दो दिनों तक जमीन पर सोए, रहे भूखे-प्यासे

इस्लामाबाद, (एजेंसी)। मलेशिया में तीन दिन पहले कंगाली की दौर से गुजर रहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के यात्री विमान को जब्त किया गया। इसके बाद वहां से किसी तरह पाकिस्तान पहुंचे यात्रियों ने जो दर्द बयां किया है वह हैरान करने वाला है। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी एयरलाइंस के यात्री विमान को जब्त करने के बाद यात्रियों को जबरदस्ती नीचे उतार दिया गया। उसके बाद न उन यात्रियों के खाने-पीने और न ही वहां पर उनके रहने की कोई व्यवस्था की गई थी।

उन पाकिस्तानी यात्रियों को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर दो दिन फर्श पर ही सोकर गुजारना पड़ा। किसी तरह अब वे यात्री पाकिस्तान स्थित अपने घर पहुंचे हैं। उन सभी का आरोप है कि मलेशिया में विमान से उतारे जाने के बाद न ही वहां के पाकिस्तानी दूतावास के स्टाफ से कोई मदद मिली और न ही पाकिस्तानी एयरलाइंस ने उनकी किसी तरह की कोई मदद की। पाकिस्तानी विमान को जब्त किए जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था कर यात्री इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वापस आने के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट के प्रबंधन की तरफ से न ही उन यात्रियों को मीडिया से बात करने दी गई और न ही उनका वीडियो लेने दिया गया।

अमेरिका में शपथग्रहण समारोह आज, अभेद्य किले में तब्दील हुई राजधानी वॉशिंगटन

वॉशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपति कमला हैरिस आज शपथ ग्रहण करेंगे। आयोजन में हथियारबंद लोगों द्वारा हिंसा की आशंका तथा अन्य खतरों के संबंध में अनेक रिपोर्टों के मद्देनजर देश की राजधानी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। बीते कुछ दिन से सुरक्षा एजेंसियों को सूचनाएं मिल रही हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा हो सकती है।

हजारों पुलिस कर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों के साथ-साथ नेशनल गार्ड के 25,000 से अधिक जवानों को यहां तैनात किया गया है। अमेरिकी संसद भवन कैपिटल के इर्द-गिर्द के इलाके, पेनसिल्वेनिया ऐवेन्यू और व्हाइट हाउस के आसपास का बड़ा हिस्सा आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है तथा इन स्थानों पर आठ फुट ऊंचे अवरोधक लगा दिए गए हैं।

हाई अलर्ट पर है पूरा शहर: पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। वॉशिंगटन डीसी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, वहीं, राज्यों के संसद भवनों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है तथा सुरक्षा अधिकारी छह जनवरी को अमेरिकी संसद भवन पर हुए भीड़ के हिंसक हमले जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कमर कस के तैयार हैं ताकि सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो सके।

पुलिस और सेना किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए तैयार

वॉशिंगटन डीसी के मेयर मुरियल बाउजर ने एक साक्षात्कार में बताया कि पुलिस विभाग संघीय कानून प्रवर्तन सहयोगियों और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। एफबीआई ने अपने आंतरिक बुलेटिन में वॉशिंगटन डीसी तथा सभी 50 राज्यों के संसद भवनों में हिंसा की आशंका जताई है।

आग्रह

भारतीय-अमेरिकी संगठनों की सुप्रीम कोर्ट से अपील

पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट को मिले जमानत

वाशिंगटन, (एजेंसी)। भारत और अमेरिका के कई नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को अपील की कि वह पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत मंजूर करे। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी) और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा आयोजित ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में संगठनों और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि हत्या के एक मामले में भट्ट की दोषसिद्धि गलत है और यह झूठे सबूतों पर आधारित है। न्यायालय 22 जनवरी को भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

पूर्व मंत्री शशि थरूर ने कहा कि वह भट्ट के साथ हुए अन्याय से क्षुब्ध हैं, जिन्हें समाज के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर सेवा करने और ताकतवर से सच बोलने की अदम्य क्षमता के कारण जेल भेज दिया गया। संजीव का मामला उस खराब दौर को दर्शाता है, जिसमें हम रह रहे हैं, जहां सभी

भारतीयों को संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक मूल्य एवं मौलिक अधिकार कई मामलों में कमजोर होते और कई बार ऐसी ताकतों द्वारा छीने जाते भी प्रतीत होते हैं, जो उदार नहीं हैं।जिन भारतीयों की अंतरात्मा संजीव भट्ट की तरह जीवित है, उन्हें खड़े होना चाहिए और इस प्रकार की चुनौतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, जो हमारे गणतंत्र के आधार को कमजोर करने का खतरा पैदा कर रही हैं।

समाज को करना चाहिए आंदोलन: पटवर्धन: प्रख्यात वृत्तचित्र फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन ने कहा कि भट्ट को इसलिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने 2002 में हुए नरसंहार का विरोध किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। पटवर्धन ने कहा कि समाज को भट्ट की रिहाई के लिए आंदोलन चलाना चाहिए।

आलोचकों के साथ रहा निश्चित एजेंडा

मानवाधिकार कार्यकर्ता, शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री मल्लिका साराभाई ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल भट्ट के मामले में उनके खिलाफ निश्चित एजेंडा चलाया जा रहा, बल्कि मोदी सरकार के अधिकतर आलोचकों के साथ ऐसा हो रहा। साराभाई ने कहा कि यदि कोई सरकार के खिलाफ बोलता है या कोई सवाल पूछता है, जो कि हमारे लोकतंत्र में प्रदत्त मौलिक अधिकार है, तो उसे किसी न किसी तरह दंडित किया जाता है। उसके खिलाफ छापे मारे जाते हैं, झूठे मामले चलाए जाते हैं और उन्हें चुप करा दिया जाता है।

भट्ट के मामले का राजनीतिक प्रबंधन बंद हो

आईएएमसी के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद ने कहा कि भारत सरकार को संजीव भट्ट के मामले का राजनीतिक प्रबंधन बंद कर देना चाहिए और सरकार से डरे हुए या स्वयं राजनीतिक बन चुके न्यायाधीशों के बजाए स्वतंत्र न्यायाधीशों की निगरानी में कानून को अपना काम करने देना चाहिए।

तीसरी और चौथी कक्षा के लिए 27 जनवरी से और पहली और दूसरी कक्षा के लिए 1 फरवरी से खोले जाएंगे स्कूल - विजय इंदर सिंगला

■ जालंधर ब्रीज/ब्यूरो

स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंदर सिंगला ने बताया कि अभिभावकों द्वारा की जा रही लगातार माँग के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने प्राईमरी क्लासों के लिए 27 जनवरी से सरकारी, एडिड और प्राईवेट स्कूल खोलने की शर्तों सहित मंज़ूरी दे दी है। विजय इंदर सिंगला ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की सहमति के बाद तीसरी और चौथी क्लास के लिए स्कूल 27 जनवरी से खुलेंगे और इसके बाद 1 फरवरी से पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में क्लासें लगाने की इजाज़त दी गई है।

उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह सुबह 10 बजे के बाद दोपहर 3 बजे तक होगा और बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावक को लिखित सहमति भी देनी पड़ेगी।

विजय इंदर सिंगला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अन्य स्कूल प्रबंधकों को स्कूल खोलने से पहले इमारतों की पूरी सफ़ाई सही ढंग से करवाने के साथ-साथ कोरोना वायरस सम्बन्धी जारी हिदायतों का सख़्ती के साथ पालन करने की हिदायत भी की है।

सिंगला ने बताया कि स्कूल खोलने और बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए जल्द ही शिक्षा विभाग की तरफ से हिदायतें ज़िला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधकों को जारी कर दी जाएंगी कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पाँचवी से लेकर बारहवीं कक्षा तक की क्लासें लगाने के लिए स्कूल खुलने के बाद से ही अभिभावक, ज़िला शिक्षा अधिकारियों और अध्यापकों द्वारा लगातार सिफ़ारिश की जा रही थी कि प्राईमरी क्लासों के विद्यार्थियों को भी स्कूलों में आकर क्लास लगाने की आज्ञा दी जाये। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनज़र अब पहली कक्षा से स्कूल खोलने की इजाज़त शर्तों सहित दी गई है।

पिम्स मेडिकल कॉलेज जालंधर में डॉ कुलबीर कौर ने कोविड वैक्सीन टीका लगवाकर की शुरुआत

■ जालंधर ब्रीज/रवि

कोविड-19 महामारी की लड़ाई के खिलाफ बड़ी जंग में चलते मंगलवार को पिम्स मेडिकल कॉलेज जालंधर मे कोविड वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई कोविड 19 वैक्सीन टीकाकरण मुहिम का जायजा लेते हुए सिविल सर्जन डॉ बलवंत सिंह ने जानकारी दी कि पिम्स जालंधर में डॉ तानिया मोद गिल (आंखों के माहिर) ने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा कर शुरुआत की इसके अलावा प्रिंसिपल पिम्स डॉ कुलबीर कोर ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया इस मौके पर उनके साथ जिला टीकाकरण अफसर डॉ राकेश कुमार चोपड़ा सहायक सेहत अफसर डॉ टी पी सिंह मौजूद थे।

सिविल सर्जन ने बताया की पिम्स के इलावा मंगलवार को सिविल अस्पताल जालंधर और एस.डी.एच नकोदर में भी फ्रंटलाइन अधिकारी और सेहत अधिकारियों की भी वैक्सीनेशन की गई इसके अलावा जालंधर के पिम्स अस्पताल में 69 जालंधर सिविल हस्पताल 25 और सिविल अस्पताल नकोदर 3 कोविड वैक्सीन के टीके लगे और उन्होंने बताया की 3 दिनों में अलग-अलग स्थानों पर कुल 392 कोविड वैक्सीन के टीके लग चुके हैं और बताया कि अभी तक जिन का टीकाकरण किया गया है।

वह सभी लाभ पत्री सेहत तंदुरुस्त है कोरोना महामारी खिलाफ लड़ाई के दौरान आगे रहने वाले सेहत अधिकारियों के काम की प्रशंसा करते हुए सिविल सर्जन ने कहा की सभी सेहत अधिकारियों ने मार्च 2020 कोविड-19 महामारी खिलाफ आगे होकर बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई जा रही है और लोगों को हर तरह की राहत और इलाज मुहैया करवाया जा रहा है।

सीआईए स्टाफ-1 जालंधर पुलिस की टीम ने अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

■ जालंधर ब्रीज/रवि

सीआईए स्टाफ-1 जालंधर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रताप बाग बिजली दफ्तर के नजदीक नाकेबंदी दौरान साजन उर्फ सन्नी पुत्र कपिल कुमार वासी मकान नंबर डब्ल्यू ए 119 चौक सूदा जालंधर और हैरीस पुत्र सुरेंद्र कुमार वासी मकान नंबर 851 आवा मुहल्ला प्रताप भाग जालंधर से पकड़ा गया। आरोपियों के बारे जानकारी देते हुए

सी.आई.ए स्टाफ के प्रभारी हरमिंदर सिंह ने बताया की इनके पास से अवैध हथियार 315 बोर पिस्तौल तीन जिंदा कारतूस बरामद किए जो वह अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की तादात में थे, आरोपियों को काबू कर उन पर मुकदमा नंबर 12 तिथि 19.01.2021 अधीन 25/54/59 आरम एक्ट थाना डिवीजन नंबर तीन में दर्ज किया और जांच के दौरान पता चला कि दोनों आरोपियों के ऊपर पहले भी सख्त धाराओं और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

केंद्र सरकार किसान विरोधी खेती कानून बिना किसी देरी के वापिस ले - तृप्त बाजवा और सरकारिया

पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा और सरकारिया किसानों के हक में दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरने में हुए शामिल

■ दिल्ली/चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के दो कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा और सुखबिन्दर सिंह सरकारिया आज जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेसी सांसदों द्वारा किसानों के हक में दिए जा रहे धरने में शामिल हुए। इस मौके पर श्री तृप्त बाजवा और सरकारिया ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों पर थोपे गए तीनों काले कानून तुरंत वापिस लेने चाहिएं।

दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि दो महीने से देशभर के लाखों किसान दिल्ली की सरहद पर कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून रद्द करने की बजाय किसान संघर्ष को पूरी तरह नष्ट करने के लिए फूट डालो और टाल मटोल की नीति पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अब तक 100 से अधिक किसानों की इस संघर्ष में जान जा चुकी है, इस सबके बावजूद भी केंद्र सरकार अभी भी किसानों से संबंधित मामले का हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, बल्कि उल्टा किसानों को डराने धमकाने के लिए ई.डी के नोटिस भेज रही है। श्री बाजवा और सरकारिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि ज़िद्द छोड़कर खुद पहल करते हुए तीनों किसान विरोधी खेती कानून रद्द करने का ऐलान करें। दोनों मंत्रियों ने यह भी स्पष्ट किया कि देशभर से न किसी किसान ने और न ही किसी राज्य सरकार ने ये थोपे गए खेती सुधारों की माँग की थी, जिस कारण पहले ही पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और सर्वसम्मति से पूरे सदन ने ये कानून रद्द कर दिए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को ये काले कानून लागू करवाने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों के दबाव से बाहर निकलकर देश के अन्नदाता के आगे सिर झुकाते हुए तुरंत ये कानून रद्द कर देने चाहिएं। इस मौके पर पंजाब के दोनों मंत्रियों ने संघर्ष कर रहे किसानों और किसान संगठनों को बधाई भी दी कि लाखों लोगों के जलसे के बावजूद इतने बड़े आंदोलन में सभी ने शान्ति बनाई हुई है।

आर.टी.आई. के जवाब ने केंद्र के झूठ का पर्दाफाश किया- कैप्टन अमरिन्दर सिंह

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

• खेती कानूनों को कमेटी की मंज़ूरी होने संबंधी झूठे दावे करने पर अकाली दल और आप को आड़े हाथों लिया • आर.टी.आई. का जवाब सार्वजनिक होने के बाद भी इसी झूठ को आधार बनाकर राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए हरसिमरत की कड़ी आलोचना

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि आर.टी.आई. के जवाब ने खेती सुधारों संबंधी उ%च-स्तरीय कमेटी द्वारा मंज़ूरी देने सम्बन्धी केंद्र सरकार के दावे का पर्दाफाश कर दिया है जिससे अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अकाली और आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली भारत सरकार के इशारों पर झूठा प्रचार किया जा रहा है जिससे दोनों पार्टियाँ मिलकर किसानों के हितों को नुक्सान पहुँचाने का काम कर रही हैं।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक योजना आयोग की तरफ से सूचना के अधिकार ऐक्ट के अंतर्गत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया कि खेती ऑर्डीनैंस और जून,2020 में संसद में इन खेती कानूनों को नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल द्वारा मुख्यमंत्रियों पर आधारित कमेटी की रिपोर्ट का मुल्यांकन किये बिना ही लाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इन दावों के उलट शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियाँ शर्मनाक ढंग से इसका प्रचार करती रहीं

जिससे भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी एजंडे को और आगे बढ़ाया जा सके। यह जिक्रयोग्य है कि केंद्रीय रा%य खाद्य मंत्री दानवे राओसाहब दादाराओ ने लोकसभा में दावा किया था कि ज़रूरी वस्तुएँ (संशोधन) बिल को उच्च-स्तरीय कमेटी ने मंज़ूरी दी थी जिसको कैप्टन अमरिन्दर सिंह स्पष्ट तौर पर रद्द कर चुके हैं और अब आर.टी.आई. के जवाब में भी यह गलत सिद्ध हो चुका है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि खेती कानूनों पर विचार-विमर्श और फ़ैसला लेने की बजाय सत्य यह है कि जैसे कि आर.टी.आई. के जवाब में भी सिद्ध हो चुका है कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल के सामने भी नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि एक बार रिपोर्ट सार्वजनिक होने जाने से सबको पता लग जायेगा कि कमेटी की मीटिंगों में किसने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि पंजाब तो कमेटी की पहली मीटिंग का हिस्सा भी नहीं था जबकि दूसरी मीटिंग में मनप्रीत बादल ने भाग लिया जिसमें कुछ वित्तीय मामले ही विचारे गए और तीसरी मीटिंग में तो सचिव स्तर के अधिकारी ही शामिल हुए।

जालंधर पुलिस (देहाती) की तरफ से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्री सुखमणि साहब के पाठ का भोग रखा गया

■ जालंधर ब्रीज/ब्यूरो

आज जालंधर पुलिस (देहाती) की ओर से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर श्री सुखमणि साहब के पाठ का भोग रखा गया। जिसके उपरांत इस शुभ अवसर पर श्री दरबार साहिब अमृतसर से हजूरी रागी कीर्तन जत्था भाई भूपेंद्र सिंह जी को आमंत्रित किया गया जिन हो ने अपने आनंद मई कीर्तन और गुरबाणी शब्दों से वहां बैठी संगत को निहाल किया। इसके अलावा सुरजीत सिंह ए.एस. आई ने दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में व्याख्या की। जिस के उपरांत सरबत

के भले और पुलिस विभाग के लिए सकुशली की अरदास करण उपरांत चाय और प्रसादे का अटूट लंगर लगाया गया।

इस मौके पर गुरप्रीत सिंह भुल्लर आईपीएस कमिश्नर पुलिस जालंधर, डॉ संदीप गर्ग आई.पी.एस सीनियर पुलिस कप्तान जालंधर देहाती, रवि कुमार आईपीएस पुलिस कप्तान स्थानक, मनप्रीत सिंह ढिल्लों पीपीएस पुलिस कप्तान तफतीश, परमिंदर सिंह हीर पीपीएस पुलिस कप्तान पीबीआई, मनजीत कौर आईपीएस पुलिस कप्तान स्पेशल ब्रांच, सुरिंदर पाल पी.पी.एस डी एस.पी पी.बी.आई, जतिंदर पाल सिंह पी.पी.एस डी.एस.पी ऑपरेशन सिक्योरिटी, हरिंदर सिंह मान पी.पी.एस डी.एस.पी आदमपुर, नवनीत सिंह महाल पी.पी.एस डी.एस.पी नकोदर, सुखपाल सिंह पी.पी. एस डी.एस.पी करतारपुर, नरेंद्र सिंह ओझला पी.पी.एस पी.बी.आई क्राइम अगेन्स्ट वूमेन, दविंदर सिंह गुहमन पी.पी.एस डी.एस.पी स्पेशल ब्रांच, अमरिंदर सिंह पी.पी.एस डी.एस.पी ट्रैफिक, रंजीत सिंह बदेशा पी पी एस डी एस पी डिटेक्टिव और समूह स्टाफ मैंबर मौजूद थे।

ब्रिसबेन की जीत के बाद रहाणे से जब पूछा गया कि कोहली के लौटने के बाद फिर उपकप्तानी संभालने पर वह कैसा महसूस करेंगे, उन्होंने कहा ," मैं इन चीजों पर सोचना नहीं चाहता। इस जीत का मजा लेना है

स्पोर्ट्स प्लैनट

कोहली की कप्तानी को खतरा नहीं लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में बढा फैब फोर का कद

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

एडीलेड से ब्रिसबेन तक बहुत कुछ बदल गया। छत्तीस रन पर सिमटने की शर्मिंदगी से गाबा का 'किला फतह' करने के बीच भारतीय क्रिकेट के युवा रणबांकुरों ने जज्बे, जीवट और जुझारूपन की नयी परिलिखी जिसे पूरी दुनिया ने सलाम किया। इस जीत ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के समीकरण भी कुछ हद तक बदल दिये। प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का कप्तान बनाने की मांग भले ही उठ रही हो लेकिन हकीकत यह है कि निकट भविष्य में किसी प्रारूप में विराट कोहली की कप्तानी को खतरा नहीं है हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों का कद जरूर बढ जायेगा। कोहली एक महीने के पितृत्व अवकाश के बाद इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के जरिये टीम में वापसी करेंगे। जब कोहली आस्ट्रेलिया से रवाना हुए तब एडीलेड में 36 रन पर सिमटने की शर्मिंदगी झेल रहे भारतीयों के सिर शर्म से झुके थे लेकिन ब्रिसबेन तक आते आते हालात पूरी तरह बदल गए।

रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा और रहाणे का कद ड्रेसिंग रूम में बढा है और उनकी बात को पहले से अधिक तवज्जो दी जायेगी। कोहली भले ही कप्तान होने के नाते सबसे आगे रहेंगे लेकिन नेतृत्व समूह में अब इन सभी का कद बराबरी का होगा। ब्रिसबेन की जीत के बाद रहाणे से जब पूछा गया कि कोहली के लौटने के बाद फिर उपकप्तानी संभालने पर वह कैसा महसूस करेंगे, उन्होंने कहा ," मैं इन चीजों पर सोचना नहीं चाहता। इस जीत का मजा लेना है और भारत लौटने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के बारे में सोचेंगे।" वैसे मुंबई का यह बल्लेबाज भूला नहीं होगा कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला से कैसे उन्हें अंतिम एकादश से बाहर किया गया था। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा के बाद सबसे ज्यादा रन बनाकर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कामयाब कप्तान के रूप में नाम दर्ज करा लिया। अश्विन ने तीन मैचों में 12 विकेट लिये और स्टीव स्मिथ को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। जल्दी ही 400 टेस्ट विकेट पूरे करने जा रहे अश्विन ने उस समय भी सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी जब मोहम्मद सिराज को नस्लीय टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा। अश्विन ने सिडनी में उस घटना के बाद कहा था ," जब सिराज ने हमें यह बताया तो मैने, रोहित और अजिंक्य ने फैसला किया कि मैच रैफरी के पास इसकी शिकायत की जाये।" पुजारा ने ब्रिसबेन टेस्ट में आस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के दिये प्रहार झेले और यही वजह है कि कोच रवि शास्त्री ने उन्हें 'वारियर' करार

दिया। रोहित चार पारियों में से तीन में सहज दिखे और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को उनकी मौजूदगी का काफी फायदा मिला। रोहित सीमित ओवरों के धुरंधर है लेकिन टेस्ट क्रिकेट की उनके लिये अहमियत का अनुमान इसी से हो जाता है कि दो टेस्ट खेलने के लिये वह सिडनी में कड़े पृथकवास में रहे। उन्होंने स्लिप में पांच कैच लपके और कई फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही। अब टीम की अगली बैठक में इन चारों सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका भी बराबरी की रहेगी और कप्तान को उनकी राय गंभीरता से सुननी होगी।

सिंधू और श्रीकांत ने थाईलैंड ओपन के पहले दौर में दर्ज की जीत

■ बैंकॉक/ब्यूरो

भारत के चोटी के खिलाड़ियों पी वी सिंधू और किदाम्बी श्रीकांत ने टोयोटा थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मंगलवार को यहां पहले दौर में सीधे गेम में जीत दर्ज की। एक सप्ताह पहले एशियाई चरण की पहली प्रतियोगिता में डेनमार्क की मिया ब्लिचफील्ड से पहले दौर में हारने के बाद विश्व चैंपियन सिंधू ने दूसरे टूर्नामेंट के शुरू में विश्व में 12वें नंबर की थाई खिलाड़ी बुसानन ओंगबमरंगफान को महिला एकल मैच में 21-17, 21-13 से हराया। सिंधू ने मैच के बाद कहा, "यह अच्छा मैच था और मैं बहुत खुश हूं। यह जीत मेरे लिये बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले सप्ताह के टूर्नामेंट में मैं पहले दौर में हार गयी थी।" इस जीत से सिंधू का बुसानन के खिलाफ रिकार्ड 11-1 हो गया है। भारतीय खिलाड़ी केवल एक बार 2019 में हांगकांग ओपन में थाई खिलाड़ी से हारी थी। सिंधू अगले दौर में कोरिया की सुंग जी ह्यून और

सोनिया चिया के बीच होने वाले मैच की विजेता से भिड़ेगी। पुरुष एकल में विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत ने थाईलैंड के सिटीकोम थम्मासिन को 37 मिनट में 21-11, 21-11 से पराजित किया। श्रीकांत पिछले टूर्नामेंट में पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दूसरे दौर से हट गये थे लेकिन अब लगता है कि वह फिट हो गये हैं। सिंधू ने बुसानन के खिलाफ 8-6 की बढ़त बनायी लेकिन थाई खिलाड़ी ने अच्छी वापसी की और एक समय वह 13-9 से आगे थी। भारतीय खिलाड़ी ने हालांकि धैर्य बनाये रखा और जल्द ही 18-16 से आगे हो गयी और फिर पहला गेम अपने नाम किया। सिंधू दूसरे गेम में अधिक प्रतिबद्ध दिखी। उन्होंने 7-2 से बढ़त बनायी और फिर ब्रेक तक 11-5 से आगे थी। सिंधू ने लगातार पांच अंक बनाकर 19-8 से बढ़त हासिल की। आखिर में उनके पास सात मैच प्वाइंट थे और उन्होंने करारा स्मैश जमाकर जीत दर्ज की।

भाजपा लीगल सेल के जिला प्रधान एडवोकेट लखन गांधी ने अपनी टीम की घोषणा की

■ जालंधर ब्रीज/ब्यूरो

आज जालंधर भाजपा लीगल सेल की एक महत्वपूर्ण बैठक श्री शीतला मंदिर भाजपा जिला ऑफिस जालंधर में हुई जिसमें भाजपा लीगल सेल के जिला प्रधान एडवोकेट लखन गांधी ने अपनी टीम की घोषणा की, इस मीटिंग में विशेष रूप में मौजूद।

सुशील शर्मा जिलाध्यक्ष,राजीव ढींगरा जनरल सेकेटरी भाजपा,अमित संध्या अधिवक्ता उपाध्यक्ष भाजपा,अर्जुन खुराना एडवोकेट जिला परवक्ता,आरके भल्ला एडवोकेट प्रभारी लीगल सेल ने उनकी टीम को सम्मानित किया ।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.